बिजली उतपादन की लागत तापीय बिजली क्षेत्र की तुलना में कम है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) देश में विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत जल विद्युत, ताप विद्युत और न्यूक्लीय है। तथापि न्यूक्लीय स्रोत का विद्युत उत्पादन अन्य दोनों स्रोतों के विद्युत उत्पादन की अपेक्षा कम है।

(ख) और(ग) वर्ष 1962-63 में समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत एवं ताप विद्युत का औसत अनुपात लगभग 50.6:49.4 था। अब 1.11.1992 की स्थिति के अनुसार देश में समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का योगदान 27.54 है। जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाना है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1987 में किए गए जल विद्युत पुर्नमूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार 60% भार अनुपात पर देश में जल विद्युत शक्यता 84040 मेगावट होने का अनुमान लगाया गया है इसकी अपेक्षा वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 600 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) जल विद्युत ताप विद्युत का प्रतिकूल मिश्रण होने का कारण, जल विद्युत परियोजनाओं की दीर्घ निर्माणाधीन अवधि होना, पर्यावरणीय समस्या, आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक परिस्थितियां, अन्तर्राज्यीय जल संबंधी विवाद तथा अधिकांश जल विद्युत शक्यता का दूर दराज के क्षेत्रों में भार केन्द्रों से दूर अवस्थित होना है।

(च) जल विद्युत उत्पादन की लागत, विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतो की अपेक्षा कम होती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की लागत

220. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1992 के दी "ओब्जवर" में "पावर जेनरेशन कास्ट 38 परसेंट चीपर इन प्राइवेट सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले विद्युत उत्पादन लागत का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने का विचार रखती है; और

(घ) क्या ऐसी जानकारी गैर-सरकारी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विद्युत उत्पादन की लागत भिन्न-भिन्न परियोजना पर भिन्न-भिन्न होती है तथा यह परियोजना के स्थान, प्रकार, क्षमता तथा अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है।

बिहार में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये योजना

221. **श्री गया सिंह:**
श्री सुनील बसुराय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा सरकार बिहार में बिजली की कमी और आवश्यकता को पूरा करने का विचार रखती है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांव संयंत्र में 1 अक्तूबर, 1992 की रात को कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कुछ अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस भीषण दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) 8वीं योजना के दौरान, बिहार में राज्य क्षेत्र में 476.9 मे०वा० तथा निजी क्षेत्र में 500 मे०वा० क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य को पूर्वी क्षेत्र में स्थापित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से भी इसका देय हिस्सा प्राप्त होगा। बिहार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु किये जा रहे अन्य विभिन्न उपायों में ये शमिल है—

विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना, पड़ोसी प्रणालियों एवं राज्यों से सहायता प्रदान करना।

(ख) कहलगांव सुपर ताप परियोजना के यूनिट-1

(210 मे०वा०) के बायलर में 9/10 अक्तूबर, 1992 को एक विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप 12 व्यक्ति मारे गये व तीन व्यक्ति जख्मी हुये।

(ग) दुर्घटना से संबंधित विस्तृत अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ही उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकेगा।

Power Transmission and Distribution in Delhi by Private Agencies

222. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal to give transmission and distribution in Delhi to private companies; and

(b) if so, what are the details of the proposal and what is its present stage?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) M/s. India Electricity Supply and Transmission Ltd. (Modi Group of Companies) has submitted a proposal for taking over generation, transmission and distribution of power in Delhi. Proposal is general in nature, without any detailed feasibility report. Government has set up a Task Force to examine the proposal and to explore the possibilities of entrusting generation, transmission and distribution of electricity in Delhi to private sector.

Excessive Billing by D.E.S.U.

223. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that D.E.S.U. has proved that when it comes to overbilling, it is second to none as per the news-item entitled "DESU 'billing' leaves residents sweltering", which appeared in the Indian Express of 22nd September, 1992;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) Keeping in view the 17.5 lakh consumers in DESU system, certain instances of defective billing cannot be avoided. The incident of disconnection of electricity of the consumer mentioned in the said news-item occurred due to inadvertant human error as two bills were being issued against the same connection. DESU has already rectified the deficiency by deleting the duplicate data in the computer. Action has also been initiated to identify other such cases and to correct the records to avoid occurrence of such incidents in future.

Plant Load Factor in U.P.

224. SHRI RAM RATAN RAM: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the Plant Load Factor for the Electricity Boards in Uttar Pradesh for the current year; and

(b) what is being done for increasing the Plant Load Factor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Plant Load Factor for thermal stations of Uttar Pradesh State Electricity Board during April 92—October 92 is 47.2%.

(b) Various measures being taken to increase the Plant Load Factor are Renovation and Modernisation of old units, assistance to Electricity Boards in undertaking Plant Betterment Programme, supply of requisite quantity and quality of coal, training of operation & Maintenance personnel, Productivity award scheme and scheme for efficient operation of thermal power stations etc.